केंद्र और राज्य में टकराव दुर्भाग्यपूर्ण

केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच राज्य के मुख्य सचिव के डेप्युटेशन को लेकर बना ताजा टकराव भी इसी कड़वाहट के लगातार विस्तार का नतीजा है। चुनावों के बाद धीरे-धीरे खत्म होने के बजाय अप्रत्याशित ढंग से खिंचती चली जा रही है।

मनमोहन वर्मा।।

पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों प्रबल प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच दिखी कड़वाहट चुनावों के बाद धीरे-धीरे खत्म होने के बजाय अप्रत्याशित ढंग से खिंचती चली जा रही है। चुनाव नतीजों के ठीक बाद यह हिंसा की घटनाओं के रूप में सामने आई। फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिश्तों में तनाव भरने लगी। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच राज्य के मुख्य सचिव के डेप्युटेशन को लेकर बना ताजा टकराव भी इसी कड़वाहट के लगातार विस्तार का नतीजा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हालिया टकराव के केंद्र में वह बैठक है, जो यास तूफान से राज्य में हुई तबाही के मद्देनजर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के उपायों पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई उस बैठक में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को आमंत्रित करने के पक्ष और विपक्ष में दी जा रही दलीलें अपनी जगह हैं, पर इस तथ्य से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि वह नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। बीजेपी उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दे रही है तो विधानसभा के इस पूरे कार्यकाल के दौरान वह सदन के अंदर और बाहर इस भूमिका में बने रहेंगे।

ममता बनर्जी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार उनकी मौजूदगी पर कहां-कहां आपत्ति करेगी। बेहतर होता, तृणमूल कांग्रेस की सरकार किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी को अपने मान-अपमान से जोड़ने के बजाय राज्य के तूफान पीड़ितों के हितों को तरजीह देते हुए पूरी गंभीरता से उस बैठक में शामिल होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केंद्र सरकार के सामने राज्य के तूफान पीड़ितों का पक्ष ढंग से रखने का एक मौका हाथ से चला गया। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले पर जिस तरह से रिएक्ट किया, उसे भी परिपक्वतापूर्ण नहीं कहा जा सकता। किसी राज्य के मुख्य सचिव को केंद्र में डेप्युटेशन पर बुलाने के इस तरीके के कानूनी पहलू अपनी जगह हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक लिहाज से भी यह कोई अच्छा कदम नहीं कहा जाएगा। मुख्य सचिव किसी राज्य के पूरे प्रशासनिक तंत्र का अगुआ होता है। उसके साथ अपमानजनक व्यवहार न केवल आईएएस अधिकारियों के बल्कि पूरे प्रशासन तंत्र के मनोबल पर असर डाल सकता है। फिर कहना होगा कि यह सब ऐसे समय हो रहा है, जब राज्य का प्रशासन कोरोना और तूफान की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है।

इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर मुख्य सचिव को तीन महीने का सेवा विस्तार इन्हीं सरकारों ने चंद दिनों पहले दिया है। साफ है कि केंद्र और राज्य की निर्वाचित सरकारें इस संकट काल में जिस तरह का रुख दिखा रही हैं, उससे कहीं बेहतर आचरण की उनसे उम्मीद की जाती है। और निश्चित रूप से वे आम देशवासियों की इस उम्मीद पर खरा उतरने की काबिलियत रखती हैं।

वरदान का अधिकार

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। सनातन के उसी भाग को बताया जहां कर्मकांड का प्रभुत्व है। हम सनातनियों को बताया ही नहीं गया कि "ब्रह्म क्या है" "कर्मयोग और ज्ञानयोग क्या है"। असल में हमें वेदों के उस भाग से वंचित कर दिया गया जो हमें स्वयं ब्रह्म होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

सनातन तो हमें "अहं ब्रह्मास्मि" के महावाक्य को आत्मसात करने का ज्ञान देता है। लेकिन गलती हमारी है कि हमने भेड़ बकरियों वाला जीवन चुना हुआ है। हम वास्तव में अपने इस मनुष्य जन्म के सही अर्थ को जानना ही नहीं चाहते। जिस मनुष्य जन्म में हमारा उद्देश्य उस ब्रह्म को जान कर स्वयं ब्रह्म होना चाहिए उस जन्म में हम तुच्छ भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करने में निकाल देते हैं। सनातन संस्कृति ने हमें अभय होने का वरदान दिया और इस वरदान को पाने का हमें अधिकार है।

संपादकीय

मिलकर बनेगी बात

भारत कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिनके हित एक से हैं, वे एक हों। सारे देश चाहते हैं कि कट्टरता और आतंकवाद अफगानिस्तान से बाहर ना निकले और उनके अंदरूनी मामलों में इससे परेशानी ना खड़ी हो। भारत भी यही चाहेगा कि पड़ोसी देश एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। अब भारत को रणनीति बनाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके समर्थन वाले स्टेकहोल्डर्स को भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में रोल मिले। कहीं ऐसा ना हो कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एकतरफा हो जाए। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि भारत, ईरान और रूस जैसे देशों के साथ एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाए। इसीलिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस जाते वक्त ईरान में भी रुके, वहां उन्होंने अफगानिस्तान पर चर्चा की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कतर ने कहा कि भारत ने तालिबान से बातचीत की है, जिसका खंडन तो भारत ने किया है, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि भारत तालिबान के साथ बैक चैनल निगोशिएशन तो कर ही रहा है क्योंकि वहां की राजनीतिक प्रक्रिया में उसकी बड़ी भूमिका होगी। इससे तालिबान और पाकिस्तान को बैलेंस किया जा सकेगा, क्योंकि अभी दिख रहा है कि तालिबान जीत रहा है और पाकिस्तान उसके साथ है। उसे तभी बैलेंस कर पाएंगे जब भारत, रूस और ईरान जैसे देश इकट्ठा होकर अफगानिस्तान का कोई ऐसा पॉलिटिकल सेटलमेंट दे पाएं, जिसमें सारे स्टेकहोल्डर्स पावर शेयर करें, न कि केवल तालिबान का वर्चस्व हो।

अफगान सरकार दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है और तालिबान ज्यादा प्रभावशाली होते जा रहे हैं। इस असंतुलन से जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर निकलकर आएगा, उसमें तालिबान केंद्र बिंदु होगा।

तालिबान का डर

हर्ष वी. पंत।।

अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं और वह क्या रणनीति बना रहा है। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी 11 सितंबर तक होनी थी, लेकिन यह उससे पहले ही हो रही है। बाइडन ने यह बात साफ कर दी है कि अफगानिस्तान में सैन्य दखल का उनका कोई इरादा नहीं है। ऐसे में जो रीजनल पावर्स (क्षेत्रीय शक्तियां) हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वहां किस तरह से शांति बहाल होती है, किस तरह से पॉलिटिकल प्रॉसेस शुरू होती है क्योंकि उनके हित वहां से सीधे जुड़े हुए हैं।

अफगान सरकार और तालिबान के बीच पॉलिटिकल सेटलमेंट अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। तालिबान इस समय हिंसा को माध्यम बनाकर अपना राजनीतिक मकसद पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक संतुलित पॉलिटिकल सेटलमेंट की संभावना कम होती नजर आ रही है। अफगान सरकार दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है और तालिबान ज्यादा प्रभावशाली होते जा रहे हैं। इस असंतुलन से जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर निकलकर आएगा, उसमें तालिबान केंद्र बिंदु होगा। फिर किस तरह से तालिबान स्थानीय शक्तियों के साथ डील करता है। ये शक्तियां

किस तरह से तालिबान के साथ डील करती हैं। यह सब अफगानिस्तान के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और भारत जैसे मध्यम दर्जे के देशों के लिए भी। वैसे तालिबान ने खुद कहा है कि अब वह 1995 का तालिबान नहीं है। तो क्या तालिबान बदल रहा है? उसका कैरेक्टर बदल रहा है? क्या उसकी विचारधारा बदल रही है? इन विषयों पर इस समय काफी बहस चल रही है, क्योंकि बाकी शक्तियां तालिबान के साथ कैसे पेश आएंगी, यह इसी पर निर्भर करता है।

यह बात भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि तालिबान ने खुद के बदलने की बात कही है। उसने यह भी कहा है कि दूसरे देशों के अंदरूनी मामले उनके लिए मायने नहीं रखते। उन्होंने कहा है कि उनकी कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि यह भारत का अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर वे हिंसात्मक राजनीति और एक मध्ययुगीन इस्लामी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, तो भारत के अंदरूनी हालात पर इसका काफी प्रभाव पड़ सकता है और आने वाले दिनों में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे दूसरे देश भी बचे नहीं रहेंगे। इसलिए वे भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। चीन इसलिए फिक्रमंद होगा क्योंकि इसका प्रभाव शिनच्यांग में पड़ेगा।

रूस इसलिए कि मध्य एशिया में अगर इस्लामिक रैडिकलिज्म या टेररिज्म फैलता है तो प्रभाव उसके यहां भी होगा। ईरान भी इससे मुश्किल में पड़ेगा क्योंकि अफगानिस्तान में सुन्नी-शिया की जो लड़ाई है, उसमें माइनॉरिटी रिफ्यूजी बनकर ईरान की ओर जाएंगे। यह होने भी लगा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से तजाकिस्तान में अफगान सेनाएं भाग गई थीं और कैसे वहां की सरकार ने उन्हें वापस भेजा। इस तरह से अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, सबके अपने-अपने हित और दुविधाएं हैं। तालिबान को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह किस तरह से इवॉल्व हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है। इसमें पारंपरिक रूप से भारत की पोजिशन यही रही है कि जो भी पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वह अफगान नियंत्रित हो। ऐसे में अफगानिस्तान में अलग-अलग पक्षों के बीच बातचीत से कोई ऐसा सेटलमेंट निकलकर आता है तो भारत को उसका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

अष्टयोग- 4936

			6		7	
4	33	4	40	7	31	2
	2		3	5		
1	29	3	37	6	35	5
		7	4		5	
6	30	2	24	1	30	3
	6		4			

प्रस्तुत खेल सुडोकु व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4935 का हल

3	5	7	4	2	1	6
1	30	2	37	6	31	3
5	1	6	3	7	2	4
6	37	3	34	1	25	5
4	7	5	6	3	2	1
7	33	4	32	4	30	2
2	3	1	4	5	6	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

नया पावर स्ट्रक्चर हो रहा खड़ा

मोहन। भारत ने रूस और ईरान के साथ नॉर्दन एलायंस को 1990 में सपोर्ट किया था। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ईरान और रूस के ऐतिहासिक संबंध हैं, जिनको बदलते जमीनी हालात में भारत रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान में भी एक नई सरकार आ रही है, नया पावर स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। ऐसे में यह वहां के लिए किसी भी विदेशी प्रतिनिधि का पहला उच्चस्तरीय दौरा था। भारत ने अफगानिस्तान को लेकर यह बात कही है कि कैसे भारत और ईरान साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद विदेश मंत्री की मॉस्को वाली मीटिंग में भी अफगानिस्तान ही छाया रहा। काफी समय तक भारत ने तालिबान से अपने संबंधों को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि काबुल में जो अफगान सरकार थी, भारत उसी को वैध मानता था और उसी को केंद्र में रखकर अपनी अफगान पॉलिसी बनाता था।